बैंकों के एन पी ए को लेकर एक नया चक्र समझ आया

रविश कुमार

राजनीतिक प्रभाव से कुछ लोग लाखों करोड़ का कर्ज़ लेते हैं, कर्ज़ वापस नहीं करते हैं। यह कर्ज़ उल्टा बैंकों पर कर्ज़ बन जाता है जिसे हम एन पी ए कहते हैं। बैंक जनता के पैसे को ही कर्ज़ पर देकर कमाई करते हैं। जितना एन पी ए हुए उतना वे जनता के कर्ज़दार हुए। इस एन पी ए की भरपाई के लिए बैंक अपने कर्मचारी अधिकारी से कहते हैं कि जनता से तरह तरह की धोखाधड़ी करो, यही नहीं बैंक उन कर्मचारी अधिकारियों के साथ भी धोखाधड़ी करते हैं। एन पी ए के कारण बैंकरों की सैलरी नहीं बढ़ती है ।लूट की यह राशि चंद हाथों में सिमट रही है और लाखों लोग सिसक रहे हैं। 26,000 खाते हैं मगर ब्रांच में दो लोग काम कर रहे हैं। लाखों बेरोज़गार नौजवान इस हिन्दू मुस्लिम और राष्ट्रवादी माहौल के नाम पर नौकरी पाने से वंचित रह गए और जो नौकरी मे हैं वो गुलाम बन गए। बैंकिंग सेक्टर की नौकरियां बहुत कम हो चुकी हैं।

उम्मीद है आपको यह फोटो समझ आ गया होगा। एक नही बल्कि सैंकड़ों बैंकरों ने लिखा है कि जब उनके पास कोई किसान कर्ज़ के लिए आता है तो उन्हें मजबूर किया जाता है कि वे किसान की ग़रीबी से थोड़ा और पैसा, जिसे आप खून भी कह सकते हैं, खींच लें। ऊपर के अधिकारी हर घंटे फोन करते हैं कि अभी कितना बीमा बेचा। गाली देते हैं कि नकारे हो, अभी तक एक भी बीमा नहीं बेचा, तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे।

बैंकर सरकार की बनाई हुई बीमा पालिसी तो बेचते ही हैं, प्राइवेट कंपनियों की पॉलिसी भी बेचने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। जबकि बैंक में बीमा बेचने या बाद की सर्विस देने का कोई ढांचा नहीं है। अगर यही काम बीमा कंपनियां खुद से करती तो लाखों लोगों को काम मिलता। मगर जनता के पैसे सैलरी लेने वाले बैंकर प्राइवेट बीमा कंपनियों की पालिसी बेच रहे हैं।

इसका गेम समझिए। आपकी जेब से ज़बरन प्रीमियम लेकर बीमा पालिसी बिकती है। इससे ऊपर वालों को मोटा कमीशन मिलता है। किसी के इशारे पर ही तो ये गेम होता होगा न। कमीशन का पैसा निकल कर कहां जाता होगा। कमीशन में भी कमीशन होता है। यही वो आवारा पैसे हैं जो चुनाव के समय नेता जी के चेहरे पर चमकते हैं और स्लोगन लिखने वालों की मौज होती है। इस सिस्टम में पब्लिक भी पीस रही है और बैंकर भी। मगर दस पांच लोगों का गिरोह ऐश कर रहा है। सारा ध्यान बीमा पर जाने के कारण भी बैंकों की कोर कमाई कम हुई है। प्राइवेट बीमा कंपनियां बैंक के भीतर दखल देने लगी हैं।आज एक बैंकर कम से कम सात आठ प्रकार के सरकारी और प्राइवेट बीमा बेच रहा है।

एक बैंकर ने लिखा है कि किसान पचास हज़ार का कृषि लोन मांगने आया। हमने कहा कि एक लाख का लोन ले लो और साथ में पचास हज़ार का जीवन बीमा भी। किसान कह रहा है कि उसे एक लाख का कर्ज़ नहीं चाहिए और वह न चुका सकता है फिर भी बैंकर उसे मजबूर करता है क्योंकि पचास हज़ार का जीवन बीमा नहीं बेचेगा तो वह घर नहीं जा सकेगा। अगले दिन बैंक के बड़े अधिकारी उसे फोन कर मां बहन की गाली देंगे। भरी मीटिंग में अपमानित करेंगे। बैंकर अपना खून बचाने के लिए किसानों का खून चूसता है।

नतीजा दोनों का ही खून चूसा जा रहा है। बैंक और ग्राहक के बीच शोषण का चक्र बन चुका है। किसान अपना कर्ज़ नहीं चुका पाता है क्योंकि वह तो पहले ही कह रहा था कि उसे एक लाख का लोन नहीं चाहिए। 50,000 का बीमा नहीं चाहिए। जिसका प्रीमियम भी उसे देना है। बैंकर ने कहा कि कई बार किसान उसका प्रीमियम लोने पर दिए जाने वाले ब्याज़ से ज़्यादा होता है। यही नहीं फसल बीमा के नाम पर हर साल किसान क्रेडिट कार्ड से बीमा राशि निकाल ली जाती है। किसान को पता तक नहीं होता है। बड़ी संख्या में भोले किसानों के साथ यह धोखा हो रहा है। उनकी जानकारी के बग़ैर फसल बीमा का प्रीमियम काट लिया जा रहा है।

आपको बता दूं कि फसल बीमा प्राइवेट कंपनियां भी करती हैं। अब आप बताइये, किसके इशारे पर, किसके हित के लिए प्राइवेट बीमा कंपनियों के लिए प्रीमियम

किसानों के खाते से काटा जा रहा है। क्या आपको यह सूदखोरी से भी भयंकर और क्रूर व्यवस्था नहीं लगती है? आप आज न कल इस हिन्दू मुस्लिम फ्रेमवर्क से निकल कर देखेंगे कि यह हुआ और जब हुआ तब चुप रहे।

किसानों की जानकारी के बग़ैर या उनकी कम जानकारी का लाभ उठाकर बीमा बेचने का यह धंधा उस भरोसे को तोड़ रहा है जिस पर बैंक कायम रहता है। क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जो ईमानदारी से इन तथ्यों को बाहर ला सके कि कितने किसानों का फसल बीमा उनकी जानकारी के बग़ैर हुआ। धोखे से दस्तख़त कराने के बाद हुआ। फसल बीमा में सरकारी बीमा कंपनियों और प्राइवेट बीमा कंपनियों की क्या हिस्सेदारी है। बैंकर चाहते हैं कि हम पत्रकार किसानों को यह बात बता दें। वैसे बीमा का दावा भी नहीं मिलता, वे बैंक आते हैं मगर दावे का निपटारा तो कंपनी करती है और कंपनी ने बीमा तो बेचा नहीं, बैंक के अफसर ने बेचा। गाली बैंक का अफसर सुन रहा है। भारत के किसान इतने साक्षर हैं नहीं, और अगर पता भी चल गया तो उस बीमा को हटाने की लंबी प्रक्रिया से गुज़रते गुज़रते दस और काम आ जाते हैं।

हर दूसरे तीसरे दिन लॉगिन डे या महा लॉगिन डे लांच होतो है, हर ब्रांच को टारगेट दिया जाता है और हर ब्रांच में अधिकारियों को टारगेट दिया जाता है। लॉगिन डे इसे इसलिए कहा जाता है कि जब तक आप उस टारगेट के हिसाब से किसानों और ग्राहकों की जेब से पैसा नहीं खींचेंगे तब तक आप लॉग आउट यानी कंप्यूटर बंद कर घर नहीं जा सकेंगे। अफसरों के कंप्यूटर पर एक सूचना फ्लैश करती रहती है कि आपका टारगेट 20 अटल पेंशन योजना और जीवन बीमा बेचने की है। बिना बेचे घर नहीं जा सकते। रात को जब ऊपर के कमांड से जब वो चेक हटाया जाता है तब जाकर बैंकर लॉग आउट करता है और ब्रांच बंद कर घर जाता है।

यह क्यों हुआ और इसे लोगों ने कैसे बर्दाश्त कर लिया? नोटबंदी और उसके बाद की यह प्रक्रिया बताती है कि आप चाहें तो लाखो लोगों को नियमित रूप से लूट सकते हैं, लाखों लोगों को रूला सकते हैं और उन्हें हिन्दू मुस्लिम और फज़ी राष्ट्रवाद के टापिक में उलझा कर रख भी सकते हैं। मैं समझता था कि आज के लोग ज़्यादा स्मार्ट हैं, बैंक सीरीज़ से एक बात समझ आ गई। लोग अब पहले से ज़्यादा नादान हैं।

बैंकों में यह प्रक्रिया शुरू तो हुई यूपीए के समय से मगर 2014 के बाद से यह आक्रामक रूप ले चुकी है। टारगेट का दबाव अब यातना प्रताड़ना में बदल चुका है। बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष बैंकर बीमार पड़ रहे हैं। लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं और जिनकी शादी हुई है उन्हें पांच पांच साल तक साथ रहने का मौका नहीं मिलता है। दो अलग अलग राज्यों में ट्रांसफर का क्या मतलब है? पांच से आठ महीने का गर्भ लेकर महिला बैंकर सौ डेढ़ सौ किमी की यात्रा कर बैंक जाती हैं। उनका पति 1500 किमी दूर पोस्टेड है। यह इसलिए किया जाता है ताकि बैंकर खुद अपनी नज़र में गिर जाएं। अपनी आवाज़ खो दें। गुलाम बन जाएं।

जब मैंने लिखना बोलना शुर किया तो आज दो बैंक के बैंकरों ने बताया कि पांच साल में पहली बार उन्हें शनिवार और रविवार को न आने के लिए कहा गया है। एक बैंकर राजस्थान के थे और एक मध्यप्रदेश के। हमने महिलाओं को शौचालय के नाम पर धमकी देने की बात उठाई तो कई बैंकों ने बकायदा लिखित आदेश जारी किया है कि महिला शौचालय का निर्माण शुरू हो और साफ सफाई भी। बैंकर थोड़े खुश हैं। मुझे बधाई दे रहे हैं।

बैंकर काम करने से नहीं कतरा रहे मगर काम करने के दौरान जो गुलामी थोपी गई है उससे घुटन हो रही है। सोचिए आप स्टेट बैंक आफ इंडिया के कर्मचारी हैं और बीमा बेच रहे हैं रिलायसं का, टाटा का या बजाज का। किस तर्क से यह सही है। जिसका जो सामान है वो अपना सामान बेचे।

बैंकरों का कहना है कि ग्राहक लेना नहीं चाहता, उसकी आर्थिक स्थिति भी नहीं है। हम उन्हें समझा ही सकते हैं मगर यह कैसे तय हो सकता है कि 20 पालिसी बेचे बिना आप घर नहीं जा सकते। कई बैंकों में लॉगिन डे और महालॉगिन डे पर बैंकर रात के नौ नौ बजे तक बैठे रहते हैं। बाहर से बैंक बंद दिखता है मगर अंदर कोई बैंकर बैठा रहता है। हम और आप लगातार इस गुलामी को मंज़ूर करते जा रहे हैं।

मैं नहीं जानता कि यह बात कितनी सही है और कैसे साबित की जा सकती है मगर बैंकरों ने ही बताई है। शाखा से कहा जाता है कि आप डिपाजिट लेकर आइये। तो ये सरकारी अधिकारी के पास जाते हैं, कंपनी के पास जाते हैं। सरकारी अधिकारी अपना हिस्सा मांगता है। प्रति करोड़ डिपाजिट पर दस से पंद्रह हज़ार रुपये रिश्वत के देने पड़ रहे हैं। एक बैंकर ने बताया कि आपस में मिलकर तीन चार लाख का लोन लिया और अब हर महीने उस रिश्वत पर 2000 से 3000 की किश्त चुकाते हैं। कई बार बैंक वाले भी इसमें हिस्सेदार होते हैं। यही नहीं बैंकों में एयर कंडीशन और स्टेशनरी की खरीद में ऊपर वाले खूब कमीशन खाते हैं। आप हम जब एसी लेंगे तो पांच सौ हज़ार की छूट दुकानदार दे ही देता है लेकिन बैंकों में सारा सामान एम आर पी पर ख़रीदा जाता है। थोक में ख़रीदने पर तो किसी को भी छूट मिलती है। इस लिए काला धन का निर्माण धड़ल्ले से जारी है।

अटल पेंशन योजना की तरह बड़ी संख्या में जनधन खाते निष्क्रिय पड़े हैं। हर शाखा में इनकी संख्या हज़ारों में हैं। प्रधानमंत्री के आंकड़ों में वह नंबर बदलता नहीं है। हम सब कई प्रकार के झूठ के साथ जीने के लिए बाध्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री भी यह सब सुनकर हंसते होंगे कि बात तो सही है लेकिन मैं तो चुनाव जीत रहा हूं। मेरा सवाल यही है आप जीत रहे हैं फिर जनता पर इतना सारा झूठ क्यों थोप रहे हैं।

बैंकरों से कहा जाता है कि आप उनमें एक एक रूपये डालकर सक्रिय करो। यह आसानी से चेक हो सकता है। अगर नागरिकों की टीम को आडिट करने दिया जाए तो तुरंत यह बात पकड़ में आ जाएगी। हम जान सकेंगे कि सरकार के फज़ी दावों के लिए बैंकरों की जेब से कितने रूपए निकले हैं और कितने जनधन खाते ऐसे हैं जिनमें कभी न कभी एक रुपये या दस रुपये डाले गए हैं।

बैंकरों को सज़ा दी जाती है। उन्हें बुलाकर रीजनल मैनेजर के कमरे में खड़ा किया जाता है। एक बैंकर तो 9 घंटे खड़ा रहा, बेहोश हुआ तो सीधा अस्पताल में और ऊपर से उसे ट्रांसफर का नोटिस थमा दिया गया। टारगेट पूरा न होने पर 50 50 साल के बैंकरों पर चीखा चिल्लाया जाता है। राजकोट से एक महिला बैंकर फोन कर रोने लगीं कि भरी मीटिंग में अपमानित किया जाता है।

बहुत सी बातचीत की ऑडियो रिकार्डिंग खुद सुनी है मैंने। एक बातचीत में अफसर कह रहा है कि तू गधा है। है कि नहीं। अफसर कह रहा है कि हां सर मैं हूं। एक रिकार्डिंग में ऊपर वाला अफसर महिला मैनेजर को गाली दे रहा है। क्या हम अपनी नागरिकता भूल गए हैं? क्या हम संविधान भूल गए हैं? शायद भूल गए हैं। हम सबकी नागरिकता का बोध ध्वस्त हो चुका है। ध्वस्त न होता तो किसान सवाल करता, ग्राहक सवाल करता। बैंकर चुपचाप नहीं सहता।

हम भारत के लोग हैं, मुख्यधारा नहीं!

हिमांशु कुमार

आदिवासियों को मुख्यधारा में लाना चाहिये , मुसलमानों को मुख्यधारा में लाना चाहिये , दलितों को मुख्यधारा में लाना चाहिये ।

कश्मीरियों को मुख्यधारा में लाना चाहिये , पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को मुख्यधारा में लाना चाहिये, दक्षिण भारतीयों को मुख्यधारा में लाना चाहिये ।

ऊपर लिखे गये ये सारे लोग मिला लिये जायें तो यह पूरा भारत हो गया , इसमे उत्तर भारत के कुछ अमीर मर्द शामिल नहीं हैं जो सुबह खाकी नेकर पहन कर पार्क मे लाठी लेकर जमा होते हैं ।

यही मुट्ठीभर मर्द भारत की मुख्यधारा तय करते हैं, यही पतली सी नाली ही मुख्यधारा घोषित कर दी गई है । तो भारत सरकार चाहती है कि भारत के सभी लोगों को इस मुख्यधारा में शामिल किया जाये ।

यानी मुसलमान औरतें अपने बच्चों को कृष्ण बनाती है तो वो मुख्यधारा मे हो जाती हैं , लेकिन जो मुसलमान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की मांग करते हैं वो मुख्यधारा के मुसलमान नहीं हैं; जो आदिवासी सेना मे शामिल होकर कश्मीर मे मारा जाता है वह आदिवासी तो मुख्यधारा का आदिवासी मान लिया जाता है, लेकिन जो आदिवासी ज़मीन और जंगल को अपना कहता है और उस जंगल पर किसी कंपनी के कब्ज़े के विरोध की लड़ाई लड़ता है , वह आदिवासी मुख्यधारा में नहीं है ।

तो भारत की मुख्यधारा का मतलब है , भारत की आर्थिक सत्ता जिन अमीर पूंजीपतियों की मुट्ठी में है उनका समर्थन करना , इन अमीरों के लिये देश के आदिवासियों , किसानों की ज़मीनों पर कब्ज़े का समर्थन करना , इन अमीरों के लिये देश की बहुसंख्य आबादी यानी किसानों , मजदूरों , आदिवासियों , छात्रों , औरतों पर लाठी चलाने वाली , गोली चलाने वाली और जेलों में ठूंसने वाले सशस्त्र सैनिकों को समर्थन देना ।

पूँजीपतियों की जेब में पड़ी हुई सरकार की हाँ में हाँ मिलाओगे तो अच्छे भारतीय माने जाओगे, संविधान में वर्णित हम भारत के लोग बनने की कोशिश करोगे तो देशद्रोही घोषित कर दिये जाओगे । मुख्यधारा का अर्थ है इन चन्द मुट्ठी भर लोगों के धर्म को पूरे देश का धर्म मानना , इन चन्द मुट्ठी भर लोगों की संस्कृति , घूंघट, पैर छूना आदि को भारतीय संस्कृति मानना ।

नागरिक होने का अर्थ यह भी मान लिया गया है कि व्यक्ति सरकार के आदेशों का पालन करे , सरकार कहे कि अपना खेत अडानी को दे दो तो किसान अपने खेत अडानी को दे दें , तब वह अच्छे नागरिक मान लिये जायेंगे ।

और अगर किसान कहें कि आपने मेरी ज़मीन छीनने के लिये मेरी बेटी के गुप्तांगों में पत्थर क्यों भरे ? और किसान सरकार के खिलाफ अदालत मे मुकदमा दायर कर दे तो ? तो वह किसान अच्छा नागरिक नहीं माना जायेगा , यानी संविधान मे दिये गये हम भारत के लोग के अधिकार के अनुसार भारत मे रहने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे ।

पूँजीपतियों की जेब में पड़ी हुई सरकार की हाँ में हाँ मिलाओगे तो अच्छे भारतीय माने जाओगे, संविधान मे वर्णित हम भारत के लोग बनने की कोशिश करोगे तो देशद्रोही घोषित कर दिये जाओगे ।

मुख्यधारा का अर्थ है इन चन्द मुट्ठी भर लोगों के धर्म को पूरे देश का धर्म मानना , इन चन्द मुट्ठी भर लोगों की संस्कृति , घूंघट, पैर छूना आदि को भारतीय संस्कृति मानना ।

बस्तर की लड़कियाँ अपनी उम्र के लड़के लड़कियों के साथ रात रात भर घूमती हैं , शादियों में बिना माता पिता को साथ लिये नाचने जाती हैं , बस्तर की युवतियां मेले मे रात भर नाचती हैं , सिर नहीं ढकतीं, पैर नहीं छूतीं , करवा चौथ का व्रत नहीं रखतीं । देश की ज़्यादातर औरतें करवा चौथ का नाम तक नहीं जानतीं लेकिन करवा चौथ को भारतीय संस्कृति मान लिया गया है , हद है ।

भारत की कोई मुख्यधारा नहीं है , करवा चौथ , पैर छूना , घूंघट करना भारत की मुख्य संस्कृति नहीं है , लड़कियों का शाम से पहले घर के भीतर घुस जाना भी भारतीय संस्कृति नहीं है , भगवान को मानना भी भारतीय संस्कृति नहीं है , करोड़ो आदिवासी, भगवान जैसे किसी जन्तु को नहीं जानते , साड़ी, बिंदी, राम, कृष्ण, पीपल की पूजा, भी भारतीय संस्कृति नहीं है ।

इस देश मे हज़ारों संस्कृतियां हैं , कोई मुख्यधारा नहीं है , मुख्यधारा के नाम पर संघ के सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का पर्दा फाश करने की ज़रूरत है ?

हमें खुद को सरकार से डरने वाला नागरिक नहीं बनाना है , हम संविधान के वह जन्मदाता हैं जो संविधान को आत्मार्पित करते है यानी खुद ही संविधान निर्माता और संरक्षक हैं ।

हम भारत के लोग हैं ।